RAJYA SABHA

Tuesday, the 28th August, 2001/6th Bhadrapada, 1923 (Saka)

The House met at eleven of the Clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Installation of Telephones in Jorhat District, Assam

*501. SHRI DRUPAD BORGOHAIN : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the normal time taken to install telephones given under MP's quota;

(b) the reasons for not installing such connections in Jorhat District of Assam Telecom circle for seven to eight months;

(c) whether it is due to the non-cooperation/indiscipline of certain lower level officials with the higher echelons of Assam Telecom Circle; and

(d) the action proposed to be taken against these officials in case of negligence and irregularities?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI RAM VILAS PASWAN) : (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The normal time taken to install telephone connections given under MP's quota is one month subject to they being technically feasible.

(b) There has been delay in providing certain connections due to their technical non-feasibility.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise in view of (c) above.

SHRI DRUPAD BORGOHAIN: Sir, after considering the urgency of telephone and going through the demand note, showing payment of money by customers, I wrote to the Chief General Manager, Assam Telephone Circle, to allot telephone connections from my M.P. quota. The office of Chief General Manager sent it quickly to the District telephone officials. But I have seen that 50 per cent of such telephone connections recommended by me last year, have not been given till date. About eight months have elapsed; it cannot be due to technical non-feasibility. So, I would like to know from the Hon. Minister whether it is an irregularity or not. If it is an irregularity, then what action will be taken to

remove it? This irregularity is there in the Jorhat Telephone District, particularly at Sibsagar and Nazira. I want the Hon. Minister's reply to this.

श्री रामविलास पासवान : सर, जैसे कि माननीय सदस्य को मालूम है कि पूरे देश में 6 लाख 7 हजार गांव हैं और हर गांव में हमारी टेलीफोन लाइन नहीं गई है और हर गांव में जाना संभव भी नहीं है ... (व्यवधान)

श्री द्रुपद बरगोहाई : इधर लाइन है।

श्री रामविलास पासवान : एक मिनट। यह दो तरह के हैं। जिस गांव में लाइन हैं, उस गांव में यदि केपेसिटी है और माननीय संसद सदस्य को नहीं दिया गया है तो I assure you that I will take an immediate action. लेकिन ऐसे गांव जहां टेलीफोन की लाइन नहीं है, दूर-दुर्गम इलाका है, पहाड़ी इलाका है वहां जैसे कि मैंने उस दिन भी कहा था कि डब्ल्यू. एल. एल. टेक्नोलाजी हमारा 6 लाख का सैंक्शन हो गया है, आ गया है। मैंने उस दिन भी यह कहा था जितने भी हमारे माननीय संसद सदस्यों के केस हैं, हमारा वी. पी. टी. का टारगेट 2002 तक है, तीन महीने के अन्दर सारी की सारी लाइनों को दे देंगे। जो कुल मिला कर के आपने दिया है उसमें आपके 6 कनेक्शन 2002 के ग्रामीण इलाके के हैं और 3 कनेक्शन 2001 के ग्रामीण इलाके के हैं और जितने भी बकाया होंगे, सब दे दिये जाएंगे।

SHRI DRUPAD BORGOHAIN: Sir, my second supplementary is this. It is reported from the customers that for months, even for years, they don't get telephone connections from the telephone authorities, even after paying the money for the connection. It is also a fact that some people get telephone connections early by bypassing other customers, although both of them belong to the category of common man. I want to know from the hon. Minister what role the 'magic' plays in this sphere. Would this irregularity be removed? Is there any mechanism to punish those who are guilty? Will the hon. Minister take some action in this regard ?

श्री रामविलास पासवान : सर, दो तरह के टेलीफोन्स हैं। एक तो मेम्बर्स आफ पार्लियामेंट का आऊट आफ टर्न है। आऊट आफ टर्न का मतलब ही होता है कि हम आऊट आफ टर्न देते हैं। इसमें जो लिस्टेड हैं उसके मुताबिक नहीं जाते हैं बल्कि पार्लियामेंट के मेम्बर्स का जो निर्धारित कोटा है उसके मुताबिक प्रायोरिटी दी जाती है। इसके अलावा जितने भी टेलीफोन्स हैं, जहां-जहां भी लाइन जाती है उस लाइन में एकार्डिंग टु जिनका डिमांड नोट पड़ा रहता है उसके मुताबिक हम जाते हैं। यदि इस तरह की इररेगुलरिटी का कहीं सवाल आता है कि कहीं फेवर किया गया है या उसमें कुछ करप्शन हुआ है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

श्री बालकवि बैरागी : माननीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद।

मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि जैसी आपके सामने परिस्थिति मूल प्रश्नकर्ता ने रखी है करीब-करीब वैसी ही परिस्थिति दिल्ली शहर की भी है और हमारे देहाती क्षेत्रों की भी है। मेरे अपने देहाती क्षेत्र में जहां गांव और कस्बे हैं वहां पर भी लम्बे समय से हम लोगों की सिफारिशें पेंडिंग पड़ी हुई हैं और उनका अभी तक फैसला नहीं हो रहा है। दिल्ली में 3 अगस्त को जो कागज दे दिए गए थे खुर्शीद लाल भवन में उन पर आज तक कार्यवाही होने की संभावना मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। बार-बार मामले टाले जा रहे हैं। मैं यहां किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन आखिर एम. टी. एन. एल. कितने दिन में दिल्ली में कनेक्शन दे देगा? एक तरफ तो हम कहते हैं कि आप मांगिए और हम कनेक्शन दे देंगे। जगह-जगह विज्ञापन होता है आपका और उसके बावजूद लोगों को टाला जाता है और तरह-तरह से उनको टरकाया जाता है। तो क्या इस दिशा में आप कुछ सख्त ऐसा कदम उठा सकेंगे या कोई समय-सीमा निश्चित कर सकेंगे कि एम. टी. एन. एल. इस समय तक दे देगा और देहाती क्षेत्रों में कब तक पूरे हो जाएंगे? डब्ल्यू. एल. एल. के नाम पर जब हम इसको तीन-तीन महीने का अब हाशिया दे रहे हैं तो उसका दुरुपयोग सब जगह हो रहा है। तो मैं माननीय संचार मंत्री महोदय से नम्रता से कहना चाहूंगा कि इस पूरी परिस्थिति की आप पुनर्वीक्षा करें और इसका कोई न कोई निर्णय आप तत्काल निकालें।

श्री रामविलास पासवान : दिल्ली में कुल मिलाकर टोटल जितने एमपीज के जो पेंडिंग हैं वे केवल 12 हैं और आप जानते हैं कि दिल्ली में भी कुछ न कुछ एरियाज टी. एन. एफ. एरियाज हैं, टेक्निकल नान फीजीबुल एरियाज। इन टेक्निकल नान फीजीबुल एरियाज में हम तेजी से काम कर रहे हैं। अभी 57 हजार हमारा जो एक्चुअल फोन्स का बैकलाग था दिल्ली का, जो एक वेटिंग लिस्ट थी, उसको हमने डब्ल्यू. एल. एल. के माध्यम से कम कर लिया है और मुश्किल से 11 हजार से भी कम बचे हैं। ये भी जो 12 हैं मेम्बर्स आफ पार्लियामेंट के इनको एक महीने के अंदर कर दिया जाएगा।

सरदार बलविन्दर सिंह भुंडर : आनरेबुल चेयरमैन साहब, आपके जरिए मैं मिनिस्टर साहब से यह कहना चाहता हूं कि क्वेश्चन तो आसाम जोरहाट का है लेकिन मैं इसके साथ ही सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो टेलीफोन ये लगाते हैं, लगने के तुरंत बाद बंद हो जाते हैं। दो-दो, तीन-तीन महीने चलते नहीं हैं। कोई कंप्लेंट सुनता नहीं है। उसका किराया आता रहता है। अगर ये पार्टिक्यूलर चाहें तो मैं दे भी सकता हूं कि कौन-कौन सी जगह कहां-कहां हैं। लेकिन जनरली जो बहुत बड़ी कंप्लेंट है उसको कब तक ये दूर करेंगे?

श्री रामविलास पासवान : टेलीफोन दो तरह के हैं। एक टेलीफोन हैं जो 'मार' टेक्नालाजी के तहत हैं। आप पंजाब से हैं। पंजाब में हंड्रेड परसेंट विलेज टेलीफोनी का टारगेट पूरा है। लेकिन यह बात सही है। मैं पिछले दिनों होशियारपुर और लुधियाना में भी था। जो 'मार' टेक्नालाजी है उसके तहत पूरे देश में 2 लाख 11 हजार गांव कवर्ड हैं। लेकिन उनमें से 80 परसेंट टेलीफोन या

तो काम नहीं करते या उनका काम सैटिसफैक्ट्री नहीं है और उन सारे का हमने टारगेट बनाया है कि उन वी. पी. टी. को हम डब्ल्यू. एल. एल. से कवर करेंगे और उस एरिया में जो भी बचेगा, उसको करके, नेक्स्ट में हम साल भर के अंदर जो 'मार' टेक्नालाजी के तहत हैं उनको भी कवर करने का काम करेंगे।

उसके अलावा हमारे यहां पूरे देश में करीब-करीब ढाई लाख किलोमीटर में पेपर इन्सुलेटिड केबल है। पेपर इन्सुलेटिड का मतलब यह होता है कि वायर के ऊपर पेपर लपेटा हुआ है। यह पूरे देश में है। आप करोलबाग के इलाके में जाएंगे तो वहां मोस्टली, यह केबल है। नतीजा यह होता है कि जहां बारिश का समय आता है तो बारिश पड़ने पर कहीं-कहीं कट जाता है वहां पेपर गल जाता है और फिर वे टेलीफोन खराब हो जाते हैं । उसके बदले में पूरे देश में आप्टिकल फाइबर ला रहे हैं। आप्टिकल फाइबर 2 लाख 40 हजार किलोमीटर में लग चुका है। इस साल का हमारा टारगेट 1 लाख 26 हजार किलोमीटर का है। पिछली बार इसका दाम बहुत बढ़ गया था, दुगना हो गया था इसलिए हमारा टारगेट थोड़ा कम रहा। इस बार दाम घट गया है आप्टिकल फाइबर का क्योंकि पिछली बार ही इतना बढ़ गया था कि अब उससे ज्यादा नहीं जा सकता था। अब घट गया है और 1 लाख 26 हजार किलोमीटर का हमारा टारगेट है। और एक बार हम चाहते हैं कि जो हमारा नेटवर्क है, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है, यदि यह बन जाएगा, रिलायेबल मीडिया से जुड़ जाएगा तो फिर टेलीफोन की खराबी का परमानेंट निदान हो जाएगा। जैसा मैंने कहा कि यह 'मार' का जो है, जिसके कारण से गांवों में खराबी है तो उसको हम बदलेंगे। दूसरा जो पेपर वायर है उसको भी बदल करके हम जैलीफ़िल्ड आप्टिकल फाइबर को पूरे देश में लगाने जा रहे हैं। एक और बात कही गई कि टेलीफोन खराब हैं, तो सात दिन से ज्यादा यदि कोई टेलीफोन खराब रहता है...... **(व्यवधान)**

सरदार बलविन्दर सिंह भुंडर : भटिंडा के एरिया में लेटेस्ट टैक्नोलोजी के मुताबिक लगाए हैं। ... **(व्यवधान)** भटिंडा की बहुत ज्यादा प्राब्लम है। जब मैं गांव में जाता हूं, आप चाहें तो मैं लिखित रूप से सभी जगह की, सभी गांवों की सूची आपको दे सकता हूं ... **(व्यवधान)**

श्री रामविलास पासवान : मैंने स्वयं कहा है और खराबी का आपको कारण बतलाया है। जहां तक आपने कहा कि खराब रहता है तो इस संबंध में मेरा यह कहना है कि यदि सात दिन से ज्यादा दिन तक टेलीफोन खराब रहता है तो फिर उस डेट का, उस पीरियड का किराये का पैसा नहीं लिया जाता है।

श्री बालकवि बैरागी : यह डेट कहां से शुरू करते हैं ?

श्री रामविलास पासवान : जिस पीरियड में सात दिन तक लगातार यदि आपका टेलीफोन खराब रहता है तो उसके लिए हमने पूरे देश में सर्कुलर जारी कर दिया है कि उस पीरियड का पैसा नहीं लगेगा, चाहे जितने दिन तक भी टेलीफोन खराब रहे।

श्री लछमन सिंह : मंत्री जी, मेरे अपने टेलीफोन में डायल टोन कटती नहीं है तो उसका क्या करोगे ? माई ओन टेलीफोन ... **(व्यवधान)** 20436 नंबर का आप स्वयं पता करा लें, जो कि मेरा अपना टेलीफोन खराब है।

श्री रामविलास पासवान : ठीक है।

श्री रमा शंकर कौशिक : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के ''क'' भाग के संदर्भ में जो उत्तर दिया है कि तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो, यह शब्द तो बहुत ही व्यापक शब्द है, इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, यह ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर पांच मीटर केबल कम है तो भी तकनीकी खराबी है, डिबिया में जगह नहीं है तो भी तकनीकी कमी है और एक्सचेंज में जगह नहीं है तो भी तकनीकी कमी है, और भी बहुत सी बातें हैं जो कि तकनीकी कमी में आ जाती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि व्यवहारिक रूप से इतना बड़ा व्यापक शब्द अगर आप दे देंगे तो आपका विभाग क्या करेगा ? दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों को जोनल दफ्तर को लिखना पड़ता है, जैसे मेरे यहां का देहरादून है। देहरादून से एक महीने में तो जी.एम. मुरादाबाद के पास चिट्ठी आती है। आप ऐसा कोई सिस्टम कीजिए कि हम लोग डायरेक्ट ही जो हमारे नज़दीकी जी. एम. हैं उनको चिट्ठी भेजें। वहां से तो दो-दो, तीन-तीन महीने तक चिट्ठी नहीं जाती। दूसरा जो ''बी'' पॉर्ट है, उसमें मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस व्यवस्था को आप बदलेंगे कि जोनल की जगह हम सीधे जी. एम. को अपनी पोस्ट भेज सकें और वह उन टेलीफोनों को लगाने का काम करें ?

श्री रामविलास पासवान : महोदय, जहां तक टेलीफोन खराबी का सवाल है, तो उसके लिए जी. एम. वगैरह और मैंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का हमारा अपना ग्रीवांसेज सैल हमने दिल्ली में ही खोल रखा है। आप हमारे यहां टेलीफोन कर दें। यदि हमारे यहां किसी को आप बतला दें, चिट्ठी का तो हम नहीं कहते क्योंकि एक तो प्रोसैस में आती है और फिर जवाब जाता है, लेकिन एक बार यदि आप अपने यहां से टेलीफोन करवा दें तो यह बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उसको तुरंत ... **(व्यवधान)**

श्री रमा शंकर कौशिक : श्रीमन्, दो साल से तो मैं विभाग को लिख रहा हूं, मेरे घर पर जो टेलीफोन लगा हुआ है वह अभी तक मेरे पार्लियामेंट के कोटे में नहीं है। दो साल से मैं लिख रहा हूँ और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हमको लिख दिया करें। मैं अपने टेलीफोन के खराब होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दो बातें कह रहा हूं, एक तो इसका जवाब नहीं ... **(व्यवधान)**

श्री रामविलास पासवान : महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैंबर ऑफ पार्लियामेंट की चिट्ठी के आधार पर छोटी से छोटी गलती के लिए मैंने हॉर्ड से हॉर्ड एक्शन लिए हैं खास करके टेलीफोन कनैक्शन वगैरह के बारे में और एक्शन इसलिए लिए चूंकि मैंने स्वयं पूछा

कि जब मिनिस्टर के कहने से, हमारे दफ्तर के कहने से तुम दो घंटे में फोन ठीक कर सकते हो तो यह सात दिन से खराब क्यों है। हो सकता है कभी-कभी हम लोगों के यहां से कहे जाने से ठीक करने के लिए दूसरा डाइवर्ट भी कर देते हो। जैसा मैंने कहा कि आप इस बात को महसूस करेंगे कि हम लोग 1977 से मैंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में रहे हैं। एक समय था कि जब टेलीफोन कितनी बड़ी प्राब्लम होती थी, आज हमारे टेलीफोन का इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रही है। पिछले साल हमारा 45 लाख का टॉर्गेट था ... (**व्यवधान**) सुनिए आप, 45 लाख के टॉर्गेट के अगेन्स्ट में हमने अब 50 लाख टेलीफोन लगाए हैं। इस बार भी हमारा टॉर्गेट 58 लाख का है, लेकिन हम उसको 80 लाख तक ले जायेंगे। इस प्रकार इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और जैसा कि मैंने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ रिलायेबल मीडिया जहां-जहां नहीं जुड़ रहा है वहां उसके कारण खराबी आती है, लेकिन उसके लिए इमीडिएट एक्शन लिया जाता है। दूसरी बात आपने कही कि कौन से तकनीकी कारण हैं। जैसे अभी आपने ही बताया तो ये बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से खराबी होती है। इसलिए उस की एक टर्म 'तकनीकी' रख दी गयी है।

श्री रमा शंकर कौशिक : श्रीमन्, मैंने जानना चाहा कि अभी हम लोगों को जोनल ऑफिस को लिखना पड़ता है और उसमें बहुत टाइम लग जाता है। जोनल ऑफिस से दो-दो महीने तक पत्र नहीं आता। इसलिए आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि हम सीधे ही जी. एम. को लिखें कि हमारे कोटे से ये टेलीफोन लगाइए। उससे जो बीच का टाइम है, वह बच जाएगा क्योंकि उस चैनल से दो-दो महीने का टाइम लग जाता है।

श्री रामविलास पासवान : ठीक है, हम उस में दोबारा जी. एम. को हिदायत देंगे। आप हम को एक चिट्ठी लिख दीजिए। हम उसे एक महीने के अंदर करा देंगे। ... (**व्यवधान**) ...सभापति जी, कई तरह के काम होते हैं, जैसे टेलिफोन कनेक्शन, टेलीफोन खराबी या दूसरा काम होता है, लेकिन कोई टेलीफोन खराब है व उसके लिए आपने जनरल मैनेजर को लिखा है और जनरल मैनेजर ने 15 दिन के अंदर उस पर ध्यान नहीं दिया तो I will take action against the General Manager. You kindly send me the details.

श्री रमा शंकर कौशिक : टेलीफोन खराबी की बात नहीं है। हम जब अपने कोटे से किसी को टेलीफोन कनेक्शन देना चाहते हैं तो हमको पहले जोनल ऑफिस को लिखना पड़ता है। मैं यह कह रहा हूं कि जोनल ऑफिस के बजाय हम सीधे जी. एम. को लिख सकें।

श्री सभापति : इन का सवाल टेलीफोन कनेक्शन का है।

...They should be allowed to write to the General Manager rather than Zonal Manager.

श्री रामविलास पासवान : सर, हम ऐसा कर देंगे कि यहां सेंट्रल लेवल पर ओ. एस. डी. के रूप में एक ऑफिसर नियुक्त कर देंगे और सभी माननीय सदस्य सीधे यही लिख दें। उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं यहीं से डील कर लिया करूंगा।

श्री रवि शंकर प्रसाद : आदरणीय सभापति जी, अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि एक महीने में एम. पी. कोटे का फोन लग जाता है। इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री जी आप प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में फोन लगाने का प्रयास करते हैं जोकि भारत सरकार की नीति भी है। लेकिन कठिनाई यह है कि कहां आप की तकनीकी व्यवस्था है और कहां तकनीकी व्यवस्था नहीं है, इस की जानकारी हमें नहीं रहती। सभापति जी, हमारे पास मित्र आते हैं, कार्यकर्ता आते हैं और जिन को फोन चाहिए वह भी आते हैं। हम उनके लिए लिखते हैं तो आप का विभाग कहता है कि वहां तकनीकी व्यवस्था नहीं है। इसलिए मेरे प्रश्न का पहला भाग यह है कि क्या आप सारे संसद सदस्यों को यह बताने की कृपा करेंगे कि कहां-कहां प्राथमिकता के स्तर पर व्यवस्था उपलब्ध है जहां पर फोन दिया जा सकता है ? अन्यथा लोग कहते हैं कि आप ने फोन दे दिया, लेकिन फोन नहीं लगता है। तो आप इस बारे में सूचना उपलब्ध कराएं, यह मेरा पहला प्रश्न है। मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि जहां-जहां व्यवस्था है वहां भी एक महीने के अंदर फोन लगने का अनुभव नहीं है। सभापति जी, मैं आप को यह सूचना देना चाहता हूं कि पटना में जहां पूरी व्यवस्था है, वहां मैंने फोन कनेक्शन के लिए पत्र लिखे हैं, लेकिन वहां भी एक महीने के अंदर नहीं लग पाता। तो क्या यह व्यवस्था और रिस्पांसिव बने, इसके लिए आप प्रयास करेंगे और तीसरा मेरा एक स्पष्टीकरण यह है कि सब जगह हिसाब मार्च से मार्च चलता है, लेकिन हम लोगों के जो सौ फोन लगते हैं, उस में हमें बताया जाता है कि 31 दिसंबर के बाद आप का कोटा लैप्स कर गया है भले ही आप ने 70 फोन लगवाएं हों या 90 लगवाएं हों। तो यह सदस्यों का जो कोटा है, वह मार्च से मार्च तक चले, इस के बारे में आप कुछ आश्वासन देंगे ?

श्री रामविलास पासवान : सर, जहां तक मार्च से मार्च तक के पीरिएड का सवाल है, उसको हम कर देंगे और आप का कोटा कंटीन्यू करेगा। आप से मेरा मतलब है, माननीय सदस्यों का, सभापति जी, मैंने नई टैक्नॉलोजी की बात की। उस में डब्ल्यू.एल.एल. के माध्यम से विलंब हुआ है। अभी उस पर डिस्कसन चल रहा है। कल दूसरे हाउस में डिस्कसन है। तो जो नई टैक्नॉलोजी हम लाना चाहते हैं, दुर्भाग्य से जब भी कोई नई टैक्नॉलोजी आती है तो उस पर बहुत डिस्कसन होता है और होना भी चाहिए। लेकिन उस में इतना टाइम लगता है कि उस टैक्नॉलोजी के सारे प्लस पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं। अब मैंने आप को एश्योरेंस दिया कि यह जो बीच का पीरिएड है, उसमें सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अधिकार है कि वह पूरे देश में किसी भी पहाड़ी इलाके में, पहाड़ के ऊपर, नदी के इलाके में और कहीं भी आप टेलीफोन कनेक्शन रिकमंड कर सकते हैं। उसमें कहीं कोई बाइंडिंग्स या रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। तो आप सब जगह करेंगे और आप

देखेंगे कि इतना होने के बावजूद भी वर्ष 1997 का एक है और वह भी मानते हैं कि वह टेलीफोन लगा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वह 'मार' टैक्नॉलोजी के तहत है और खराब है। उसी तरह से 1998 में इक्कीस हैं। पूरे देश में 1999 के कुल मिलाकर 263 बचे हैं। उसी तरीके से आज तक, इस साल अभी तक, कुल मिलाकर ये करीब 11,000 हैं। हमने नई टैक्नोलॉजी आने के दिन ही कह दिया था कि आप हमको तीन महीने का, दिसम्बर तक का मौका दे दीजिए, उसके बाद एम.पीज़. को जो हमने ऐश्योरेंस दिया है कि महीने में लग जाएगा, वह हो जाएगा, हालांकि यह हमारा ऐश्योरेंस नहीं है, यह बहुत पहले से चला आ रहा है। हम लोग जब मंत्री नहीं थे तो हम लोगों की भी ऐसी शिकायत रहती थी। इसलिए दिसम्बर के बाद जो एक महीने का टारगेट है, वह टारगेट हम पूरा कर दिया करेंगे।

SHRI K. RAHMAN KHAN : Sir, the hon. Minister has stated that telephones are not installed in time due to technical reasons. I agree with Mr. Ravi Shankar Prasad that no telephone is installed within a month. They say, "Technical feasibility is not there". But there have been a number of instances where when a person gives some money to the lower staff of the Telephone Department, the telephone is installed within 24 hours. Does it not put the MPs in a very awakward situation? When a person talks to the GM, he says, "Technical feasibility is not there", but when the same man gives some money to the lower staff, the telephone is installed within 24 hours. So, why don't you take action in such cases? Will the Minister inquire into this matter and find some solution? The second part of my supplementary is, as it is in the case of MPLADS funds, the telephone quota should not be allowed to lapse. It should be allowed to be given after that period also.

श्री रामविलास पासवान : सर, मैंने पहले ही कह दिया कि जहां तक फोन के कोटे का सवाल है, वह लेप्स नहीं होगा, आपने जो एप्लाई नहीं किया है, वह दूसरे साल में आएगा। जहां तक आपके सवाल के दूसरे भाग का प्रश्न है, तो यह तो एक बिजनेस है और अब प्राइवेट सैक्टर के सब लोग इसमें आ चुके हैं और जितनी टेलीफोन की लाइनें लगेंगी, उतना डिपार्टमेंट को भी फायदा होगा। एम. पी. अगर किसी के नाम टेलीफोन रिकमेंड करते हैं तो जिनके नाम की रिकमेंडेशन होती है उनको टेलीफोन फ्री तो नहीं मिलता है, उनको भी पैसा तो देना ही पड़ता है। इसलिए यह तो बिजनेस है और उसमें अगर डिपार्टमेंट धीमी गति से चलेगा तो पिछड़कर रह जाएगा। इसलिए वह नहीं है।

जहां तक आपने दिल्ली के एरिया के बारे में कहा, तो दिल्ली का कुछ एरिया है अदरवाइज दिल्ली का 80 परसैंट एरिया ऐसा है जहां एप्लाई करने के 10-15 दिन में टेलीफोन मिल रहा है।

अभी हम बिजनौर गए थे, हमारे लोक सभा के एम.पी. हैं रवि जी और बिजनौर के जो कोई साथी यहां हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि बिजनौर में एप्लाई करने के एक हफ्ते के अंदर, बिना कहे, टेलीफोन मिल जाता है। हमारा यह भी टारगेट है कि कम से कम जितने शहरी इलाके हैं, उनमें 2002 तक टेलीफोन ऑन डिमांड कर दें। शिकायतें हैं, मैं इसमे इन्कार नहीं करता। देश में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पूरी तरह से परफेक्ट हो, शिकायतें तो हैं लेकिन जिस तरीके की पिक्चर आप बता रहे हैं और खासकर एम.पी. अगर किसी को रिकमेंड करे और एम.पी. की रिकमेंडेशन के बाद भी यदि कोई अफसर किसी चीज़ की मांग करे तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही गंभीर मामला है और यदि जरा सा भी आप हमको इस बारे में कुछ दे दें और हल्का सा भी हमको इस बारे में कुछ मिल जाए तो मैं ऐक्शन ले लूंगा।

श्री के. रहमान खान : यह बात बिल्कुल सही है, इसमें आप कोई शक मत कीजिए।

श्री रामविलास पासवान : मैं यह तो नहीं कर रहा हूं कि आप गलत बोल रहे हैं लेकिन आज के युग में टेलीफोन कनेक्शन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रह गई है और उसके लिए एम.पी. के कहने के बावजूद भी अगर अधिकारी उस तरीके का बर्ताव करे तो मैं उसके खिलाफ ऐक्शन लूंगा।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : यह आम बात है । **(व्यवधान)**

सरदार गुरुचरण सिंह तोहड़ा : मान्यवर चेयरमैन साहब, मैं इस बात को मानता हूं कि मौजूदा मिनिस्टर साहब ने टेलीफोन कनेक्शन भी बहुत दिए हैं लेकिन यह भी सही है कि टेलीफोन खराब होने की शिकायतें भी उतनी ही बढ़ी हैं।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां मोबाइल फोन सेवा दिल्ली से 2 रुपए महंगी है। इसका क्या कारण है कि मोबाइल फोन सेवा पंजाब में महंगी है, दिल्ली से 2 रुपए महंगी है और हरियाणा से एक रुपए महंगी है। ये दो स्टेट्स हैं, इनके साथ ऐसा पक्षपात क्यों हो रहा है ? क्या मंत्री जी इसे खत्म करेंगे ?

श्री रामविलास पासवान : सभापति महोदय, मोबाइल फोन सेवा का जहां तक सवाल है, इसमें अभी तक प्रत्येक सर्किल में 2-2 प्राइवेट ऑपरेटर्स के काम करने का प्रावधान था लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, जिनमें पंजाब भी है, बिहार भी है, जहां 2-2 ऑपरेटर्स तो थे लेकिन एक ऑपरेटर किसी कारण से काम नहीं कर रहा है या उसका लाइसेंस रद्द होने के कगार पर है, इसलिए वहां एक ही ऑपरेटर काम कर रहा है जिसकी वजह से उसकी मोनोपोली हो गई है। यह हमारे हाथ में नहीं है। इसके लिए रेगुलेटर है, इसके लिए टी.आर.ए.आई. है, उनके पास शिकायत जाती है। हम इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं। हम इतना ही कर रहे हैं कि NTP, 1999

के अंतर्गत अब 4 ऑपरेटर्स मैदान में हैं, इस प्रकार 2 की जगह 4 ऑपरेटर्स हो गए हैं जिनमें BSNL भी शामिल है। जहां तक BSNL का सवाल है, हमारा टॉरगेट है कि इस साल के अंत तक पूरे देश में हम अपनी सेवा शुरू करेंगे। जैसा कि आपने दिल्ली के बारे में कहा, दिल्ली में आप देखिए कि जब तक MTNL मार्केट में नहीं आया था, तब तक रेट 4 रुपए के करीब था और ज्यों ही MTNL की मोबाइल सेवा शुरू हुई तो अब कंपीटीशन के कारण रेट कम होकर 2 रुपए पर आ गया है। इसी तरीके से हम कंपीटीशन ला कर दाम कम करेंगे लेकिन जहां तक इनके द्वारा चार्ज किए जाने का सवाल है, उस पर हमारा कोई बस नहीं है, वह टी.आर.ए.आई. के अधिकार क्षेत्र में आता है।

श्री नरेन्द्र मोहन : सभापति जी, मंत्री जी ने जो टेलीफोन व्यवस्था का विकास किया, इसके लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं लेकिन टेलिफोनों की जो खराबी है, राष्ट्रीय स्तर पर 100 टेलीफोनों में कितने खराब रहते हैं, इनके पास निश्चित रूप से ये आंकड़े होंगे, मैं उन आंकड़ों को जानना चाहूंगा। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि दिल्ली में जो हमारी स्थायी समिति के सामने मामले आए थे, उनमें यह बताया गया था कि 100 टेलीफोनों में से लगभग 30 टेलीफोन खराब रहते हैं आखिर यह स्थिति क्यों है ? देश की राजधानी में 100 टेलीफोनों में से 30 टेलीफोन अगर खराब रहते हैं तो यह अपने आप में गंभीर मामला है। प्रगति हो रही है लेकिन यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका कोई समाधान अगर मंत्री जी के मस्तिष्क में हो तो कृपा करके बताने का कष्ट करें।

श्री रामविलास पासवान : सभापति महोदय, टेलीफोन का विकास और खराबी, ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। इस बार हमारा टारगेट था कि यह खराबी 11 परसेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ इलाकों में जैसे दिल्ली में हमने right of way सभी प्राइवेट ऑपरेटर्स को दे दिया है ताकि वे अपनी केबल भी लगा लें। उसमें कहीं-कहीं कोआर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। दिल्ली में यदि 5 प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, वहां कोई common duct तो है नहीं, नीचे जहां MTNL की लाइन है, वहीं किसी दूसरे ऑपरेटर ने भी खुदाई कर दी और पहले वाली लाइन कट गई, इस तरह लाइन कटने के बाद का टेलीफोन खराब हो जाता है। इस तरह के यहां बहुत से ऐरियाज़ हैं। इसके लिए हमने प्रत्येक राज्य सरकार को लिखा है कि आप कोई ऐसी कोआर्डिनेशन कमेटी हर राज्य में बनाइए जिससे कि जो भी अपनी टेलीफोन की लाइन कहीं लगाना चाहे, उसके लिए उन्हें छूट हो, उनसे पैसा भी लिया जाता है सड़क की मरम्मत के लिए लेकिन वे कम से कम एक-दूसरे की लाइनों का अतिक्रमण न करें। अब तो नयी टेक्नोलॉजी आ गई है, आप्टिकल फाईबर्स वगैरह आ गए हैं, पहले हम लोग पढ़ते थे कि उसमें 9 रंग होते थे, अब तो हजारों रंग आ गए हैं, उसमें अगर कहीं कट गया तो एक-दूसरे को जोड़ने में काफी समय लगेगा।

श्री नरेन्द्र मोहन : हमें कारण नहीं जानने हैं। यह तो क्षरण हुआ है। आखिर इस समस्या का समाधान करना होगा।

सभापति जी, दिल्ली जैसे शहर में एक तिहाई टेलीफोन खराब पड़े रहें, इसका कोई औचित्य नहीं है।

श्री रामविलास पासवान : सर, मैंने कहा कि पहले जितने टेलीफोन खराब रहते थे उसमें कमी आई है। उन्होंने दिल्ली के बारे में प्रश्न पूछा इसलिए मैंने दिल्ली के बारे में जवाब दिया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि टेलीफोन की जो खराबी है या गड़बड़ी होती है उसमें सतत सुधार हो रहा है। चूंकि लाईन की संख्या बढ़ रही है इसलिए नम्बर भी थोड़ा बढ़ रहा है।

DR. ALLADI P. RAJKUMAR : Sir, I request you to allow us to have a Half-an-hour Discussion on this subject. There are so many problems relating to telephones. Even my telephone in Hyderabad has been lying out of order for the last 15 days. Nobody has come to repair it yet. After listening to the problems faced by so many Members, I request you to kindly allow a Half-an-hour Discussion on it. It is not only in Andhra Pradesh that we are facing this problem the people in other States also must be facing the problem. The hon. Minister is capable enough but his mere presence in the House is not enough. Let us be practical. When he has held a meeting with the General Managers, let him send a copy of the minutes to all the MPs. The General Managers will not speak to us. There are so many problems that we have been facing. Kindly allow Half-an-hour Discussion on the subject.

श्री रामविलास पासवान : सर, हाफ-एन-ऑवर कर दीजिए, दो घंटा कर दीजिए, लेकिन मैंने तो कह दिया कि मैं मेंबर्स आफ पार्लियामेंट के लिए यहां पर एक अफसर नियुक्त कर रहा हूं उनके टेलीफोन की खराबी के लिए। मैं कहना नहीं चाहता हूं कि किसी मेंबर आफ पर्लियामेंट के पास 100 रिकमंडेशंस हैं और कुछ मेंबर आफ पार्लियामेंट आ जाते हैं 25 नाम एकस्ट्रा लेकर के, मैं न तो किसी को नहीं कहता हूं, मैं उसको भी कर देता हूं। हम लोग यहां रोज बैठते हैं, आप कह सकते हैं। जो भी मेंबर आफ पार्लियामेंट है, आप लिखकर दे दीजिए किस-किस टेलीफोन की क्या खराबी है और यदि मेंबर आफ पार्लियामेंट के टेलीफोन की खराबी के लिए आप कहते हैं सात दिन, लेकिन मैं कहता हूं कि यदि तीन दिन से ज्यादा खराब रहेगा तो मैं उसको सस्पेंड कर दूंगा। आप लिखकर दे दीजिए I will take action. I am very serious on this. यदि मेंबर आफ पार्लियामेंट का टेलीफोन तीन दिन, पांच दिन, सात दिन तक खराब रहे तो उस अफसर को काम करने का कोई अधिकार नहीं है। But you kindly give me the complaint in writing.

श्री राजू परमार : पासवान जी, साथ में पब्लिक का भी 7 दिन में कर दीजिए।... (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : मैं कहता हूं कि किसी भी मेंबर आफ पार्लियामेंट का टेलीफोन 7 दिन से ज्यादा खराब नहीं रह सकता। यदि रहता है तो I will take action against them if the telephone remains out of order.

श्री संघ प्रिय गौतम : पब्लिक का भी कर दीजिए, मेंबर आफ पार्लियामेंट का ही क्यों ?

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा : मेरा टेलीफोन काफी दिन से खराब पड़ा हुआ है और बिल भी आ रहा है।...(**व्यवधान**)

श्री रामविलास पासवान : यह बात साफ हो जानी चाहिए कि यदि मेंबर आफ पार्लियामेंट बिल जमा नहीं करेंगे क्योंकि टेलीफोन खराब है और आप कह देंगे कि हमारा टेलीफोन कटा हुआ है then the Officer will not be held responsible.

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी : सर, एक बात कहने की इजाजत चाहता हूं जो लोग बिल जमा नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो कानून अपना काम करेगा लेकिन जो लोग बिल जमा कर रहे हैं और उसके बावजूद टेलीफोन खराब रहता है और कहने के बाद भी लोग ठीक करने नहीं आते हैं और बिल भी नहीं भेजते हैं उनका क्या है ? मैं अपनी बात आपको बतांऊ, मैं बिहार से आता हूं, अब तो झाड़खंड से आ रहा हूं, वहां बिल नहीं आता है। यहां के अफसरान मुसलसल लिखते रहते हैं कि खुदा के लिए बिल तो भेज दीजिए और नहीं भेजते हैं। तो उस पर क्या कार्रवाई होगी ? उसका आश्वासन दे दीजिए कि वे बिल भेजेंगे।

श्री रामविलास पासवान : सर, मैं कहना नहीं चाहता हूं लेकिन मैं कई मेंबर आफ पार्लियामेंट का नाम जानता हूं। मेरे पास आए कि साहब, हमारे टेलीफोन का इतने लाख रुपए का बिल आया है। मैंने कहा कि मिनिस्टर के पास में कोई अधिकार नहीं है एक नए पैसे के बिल को माफ करने का। यदि आपका बिल गलत आया है तो मैं गलत बिल के बारे में आपको बतला सकता हूं कि कहां-कहां टेलीफोन किया गया है। हम टेलीफोन करने की सूची इसलिए प्रकाशित नहीं करते हैं कि बहुत से लोग उसको लाइक नहीं करेंगे कि हमने कहां-कहां टेलीफोन किया इसलिए जो मांगता है उसी को देते हैं कि किसने, किसको टेलीफोन किया है। सर, इसलिए ...(**व्यवधान**)... सर, मैंने कई केसिज में एक्जामिन करवाया है और अंत में उन्हीं मेंबर आफ पार्लियामेंट ने कहा है ...(**व्यवधान**)...

श्री लछमन सिंह : मंत्री जी लिस्ट दे दीजिए...(**व्यवधान**)...

श्री रामविलास पासवान : आप सुनिए। आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...सर, उसी मेंबर आफ पार्लियामेंट ने बाद में कहा कि हां, टेलीफोन तो ठीक हुआ था लेकिन आप माफ कर

दीजिए। हमने कहा कि माफ करने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि टेलीफोन की गड़बड़ी के या कनेक्शन कटने के बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि जहां किसी की वजह से मेंबर आफ पार्लियामेंट का या, आपके द्वारा अनुशंसित या किसी के द्वारा अनुशंसित मामला हमारी नॉलेज में आता है तो हम एक्शन लेते हैं। मैंने फिर कहा कि यदि मेंबर आफ पार्लियामेंट का या किसी का टेलीफोन बिना किसी वजह से यदि एक सप्ताह क्या, पांच दिन से भी ज्यादा खराब रहेगा तो कार्यवाही की जाएगी। आप लिखकर दे दीजिए। मैं विजीलेंस से इन्क्वारी करवाकर एक्शन लूंगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं उस अफसर को सस्पेंड भी कर दूंगा।

डॉ. अलादी पी. राजकुमार : सर, ठीक है। मैं मिनिस्टर साहब को लिखकर दे रहा हूं।

श्री रामविलास पासवान : ठीक है। दे दीजिए ...*(interruption)* ... Sir, by evening, I will let him know the real position. I will also send you a copy of it.

श्री राजू परमार : मंत्री जी, आप ऐसे पब्लिक का भी कर दीजिए।

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD : Mr. Chairman, Sir, Question No. 502 regarding SEBI is very important.

MR. CHAIRMAN : The concerned Members are not here.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD : Sir, it is surprising that when the question came up, the concerned Members are not present.

MR. CHAIRMAN : Members are not there.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD : This question on SEBI is very important.

MR. CHAIRMAN : Question No. 504, Mr. Bhagatram Manhar.

*502. [The Questioners (Shri Munavvar Hasan and Miss Mabel Rebello) were absent. For answer *vide* Page 27 in fra.]

*503. [The Questioner (Dr. Mahesh Chandra Sharma) was absent. For answer *vide* Page 27—28 *infra*.]